कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में इस समय लगभग 15 चावल जोन हैं। उत्तरी और दक्षिणी चावल जोन, जहां प्रत्येक जोन में कुछ राज्य शामिल हैं, को छोड़कर अन्य जोन लगभग एक राज्यीय जोन है। दक्षिणी चावल जोन में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु और पांडिचेरी के चावल उपभोक्ता क्षेत्र शामिल हैं। राजस्थान के उपभोक्ताओं की चावल की बढ़िया किस्म की मांग को पूरा करने में सहायता करने के लिये राजस्थान को उत्तरी चावल जोन में शामिल कर लिया गया है।

(ख) स्थिति, जोकि समय-समय पर बदलती रहती है, की जरूरत के मुताबिक चावल जोन बनाये जाते हैं, उनका विस्तार किया जाता है। 1976-77 विपणन मौसम के दौरान, क्षेत्र के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी चावल जोन बनाया गया है।

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

970. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी पर से नियंत्रण हटाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) और (ख) : सरकार चीनी नीति पर जब अगली बार विचार करेगी तब अन्य प्रश्नों के साथ-साथ चीनी से नियंत्रण उठाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

Reimbursement to the allottees of Rajouri Garden Flats

971. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the price of the DDA (LIG) Flats at Rajouri Garden (G-8) was higher than the price of DDA (LIG) Flats at Prasad Nagar and Kalkaji;

(b) if so, the reasons for this anomaly; and

(c) whether Government are considering for suitable reimbursement to the allottees of Rajouri Garden flats?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT : (a) Yes, Sir.

(b) The difference in price of flats arises due to difference in design, plinth area and the rate at which the work is awarded.

(c) No, Sir.

Memoranda from Individuals/Institutions of Maharashtra regarding Education Policy

972. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) how many representations and memoranda have been received by the Government since 25th March, 1977 from individuals and institutions of the State of Maharashtra in regard to educational policy of Government; and

(b) what action Government have taken or propose to take in respect of the said representations and memoranda?